

अडानी निवेश से पांच शेयरों में तेजी

चालू वित्त वर्ष में करीब 2.1 लाख करोड़ और अगले पांच साल में 125 अरब डॉलर निवेश की योजना

मुंबई, 10 अगस्त अडानी समूह की रिकॉर्ड पूंजीगत खर्च योजना का असर अब समूह की कंपनियों से आगे बढ़कर उन कंपनियों पर भी दिखाई देने लगा है, जो उसके बड़े बुनियादी ढांचा, बिजली, ग्रिड और निर्माण प्रोजेक्ट्स के लिए सामान और सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं।

समूह की ओर से आने वाले वर्षों में भारी निवेश किए जाने की तैयारी के बीच इन क्षेत्रों से जुड़ी कंपनियों की ऑर्डर बुक में तेज वृद्धि हुई है। इसका असर शेयर बाजार में भी दिखाई दे रहा है। हितवाची एनबी ईडिया का शेयर पिछले दो वर्षों में करीब 197 प्रतिशत चढ़ चुका है, जबकि



सेमईडिया प्रोजेक्ट्स में करीब 152 प्रतिशत और जीई वनॉवा टीएंडडी इंडिया में करीब 147 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं बीएचईएल का शेयर एक साल में करीब 79 प्रतिशत और पीएसपी प्रोजेक्ट्स करीब 39 प्रतिशत मजबूत हुआ है। अडानी समूह ने मार्च 2026 में समाप्त वित्त वर्ष में करीब 1.53 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत खर्च किया। इसे किसी

भारतीय कॉरपोरेट समूह की एक साल में की गई सबसे बड़ी पूंजीगत खर्च राशि में से एक माना जा रहा

अडानी समूह की ओर से कंपनी में 34.41 प्रतिशत हिस्सेदारी लेने के बाद वित्त वर्ष 2026 में इसकी ऑर्डर बुक 85 प्रतिशत बढ़कर 13,447 करोड़ रुपये हो गई। इसमें करीब 67 प्रतिशत हिस्सा अडानी समूह से जुड़े प्रोजेक्ट्स का है। हालांकि, ऑर्डर बुक में तेजी के बावजूद कंपनी का पूंजी पर रिटर्न घटकर 7 प्रतिशत रह गया और कार्याशील पूंजी चक्र 65 दिन से बढ़कर 96 दिन हो गया। यानी ऑर्डर बढ़ने के साथ मुनाफे और नकदी प्रवाह में उसी अनुपात में सुधार अभी चुनौती बना हुआ है।

है। खास बात यह है कि इस खर्च का करीब 80 प्रतिशत हिस्सा बाहरी आपूर्तिकर्ताओं और कंपनियों के जरिए किया गया। अब समूह चालू वित्त वर्ष में करीब 2.1 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत खर्च करने की तैयारी में है। इसके अलावा अगले पांच वर्षों में विभिन्न कारोबारों में करीब 125 अरब डॉलर निवेश की योजना है।

महिलाओं को रोजगार के लिए मिलेंगे 2 लाख रुपये

नई दिल्ली, 10 अगस्त सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना महिलाओं को अपना रोजगार शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खातों में शुरुआती तौर पर 10 हजार रुपये की राशि सीधे भेजी जाती है। इस रकम का इस्तेमाल महिलाएं छोटा व्यवसाय या स्वरोजगार शुरू करने के लिए कर सकती हैं। सरकार बाद में यह देखती है कि महिला ने रोजगार शुरू किया है या नहीं और उसका काम किस तरह आगे बढ़ रहा है। लगभग छह महीने बाद रोजगार की प्रगति के आधार पर अतिरिक्त सहायता का प्रावधान है। पात्र महिलाओं को कारोबार विस्तार के लिए 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता मिल सकती है।

अमेरिका-ईरान तनाव के बीच बाजार सपाट

78,502 पर खुला
संसेक्स

24,581 पर पहुंचा
निफ्टी

मुंबई, 10 अगस्त.अमेरिका और ईरान के बीच होमर्जु जलडमरूमध्य को फिर से खोलने को लेकर जारी अनिश्चितता के बीच भारतीय शेयर बाजार ने सोमवार को समाह के पहले कारोबारी दिन सपाट शुरुआत की। शुरुआती कारोबार में संसेक्स और निफ्टी में मामूली बढ़त दर्ज की गई, हालांकि बाद में बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिला।

30 शेयरों वाला बीएसई संसेक्स पिछले बंद 78,499.17 के मुकाबले 2.41 अंक की मामूली बढ़त के साथ 78,501.59 पर



खुला। वहीं एनएसई निफ्टी-50 10.59 अंक बढ़कर 24,581.25 पर पहुंचा। शुरुआती कारोबार में संसेक्स करीब 177 अंक यानी 0.22 प्रतिशत चढ़कर 78,676 के स्तर तक पहुंच गया, जबकि निफ्टी 0.20 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,620 के आसपास कारोबार करता दिखा। हालांकि, बाद के कारोबार में बाजार की तेजी कुछ

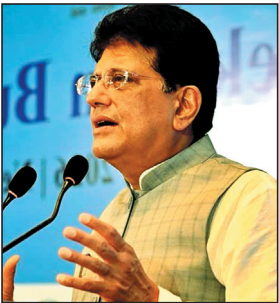
कमजोर पड़ गई। व्यापक बाजार में निफ्टी मिडकेप 0.21 प्रतिशत मजबूत रहा, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप में 0.13 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। क्षेत्रवार कारोबार में निजी बैंक, ऑटो, आईटी, धातु, फार्मा और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं से जुड़े शेयरों में मजबूती रही। दुधरी और, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, मीडिया, एफएमसीजी और तेल-गैस क्षेत्र दबाव में रहे। निफ्टी-50 में टाइटेन कंपनी, टेक महिंद्रा, टाटा स्टील, ग्रासिम, सिप्ला, इंफोसिस और ट्रेट शुरुआती कारोबार में प्रमुख बढ़त वाले शेयर रहे।

पिछले समाह अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के समझौते के करीब पहुंचने के संकेतों से बाजार में उम्मीद बढ़ी थी। हालांकि, बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका तेहरान के साथ केवल आंशिक बातचीत कर रहा है और आर्थिक दबाव जारी रखने का इरादा रखता है। होमर्जु जलडमरूमध्य वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण मार्ग है।

जेम से सरकारी खरीद में पारदर्शिता बढ़ी : उद्योग मंत्री

जेम पर 1.37 लाख से अधिक
सरकारी खरीदार पंजीकृत

करीब 25 लाख विक्रेता और सेवा
प्रदाता जुड़े



नई दिल्ली, 10 अगस्त वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि सरकारी ई-मार्केटप्लेस यानी जेम ने देश में सरकारी खरीद की व्यवस्था को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। करीब एक दशक पहले महज 422 करोड़ रुपये के सकल कारोबार मूल्य से शुरू हुआ यह मंच अब 1.55 लाख करोड़ रुपये से अधिक के स्तर पर पहुंच गया है।

गोयल ने कहा कि जेम ने सरकारी खरीद में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के साथ बेहतर कीमत सुनिश्चित करने, खरीद प्रक्रिया में लगने वाला समय घटाने और पूरी व्यवस्था को डिजिटल बनाने में अहम योगदान दिया है।

पोर्टल पर फिलहाल 12.28 लाख से अधिक सूक्ष्म एवं लघु उद्यम पंजीकृत हैं। इनमें 2.25

लाख से अधिक महिला उद्यमियों द्वारा संचालित प्रतिष्ठान शामिल हैं। इसके अलावा 42 हजार से अधिक नए उद्यम भी जेम से जुड़े हैं। मंत्री के मुताबिक, इस मंच ने छोटे कारोबारियों, महिला उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों, कारीगरों और बुनकरों के लिए सरकारी बाजार तक पहुंच आसान की है। 9 अगस्त 2016 को शुरू हुआ जेम अब अपने 11वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है।

पोर्टल पर 1.37 लाख से अधिक सरकारी खरीदार संगठन और करीब 25 लाख विक्रेता एवं सेवा प्रदाता जुड़े हुए हैं। यहां सरकारी जरूरतों के लिए 10,660 से अधिक उत्पाद श्रेणियां और 350 सेवा श्रेणियां उपलब्ध हैं।

गोयल ने कहा कि जेम 'स्थानीय के लिए मुखर' और 'भारत में निर्माण' जैसी पहलों को भी बढ़ावा दे रहा है। सरकारी मांग को स्थानीय कारोबारियों से जोड़ने से छोटे उद्यमों को बड़ा बाजार मिल रहा है। इससे आत्मनिर्भरता और समावेशी आर्थिक विकास को भी मजबूती मिल रही है। सरकार अब जेम को और अधिक आधुनिक तथा एकीकृत बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसके तहत कुटुिम बुद्धिमत्ता के इस्तेमाल और अधिक लोगों की भागीदारी के जरिए सरकारी खरीद व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, तेज और प्रभावी बनाने पर जोर दिया जा रहा है।

स्मार्ट बाज़ार ‘फुल पैसा वसूल सेल’ वापस ला रहा है

मुंबई, 10 अगस्त. रिलायंस रिटेल का वैल्यू-लेड सुपरमार्केट ब्रांड, स्मार्ट बाजार, 12 से 16 अगस्त तक अपनी बहुप्रतीक्षित 'फुल पैसा वसूल सेल' वापस ला रहा है, जिससे ग्राहकों को अपनी रोजाना की घरेलू खरीदारी पर बचत करने के ज़्यादा तरीके मिलेंगे।

ग्राहकों को इस आम सच्चाई पर बनी कि परिवार के लिए खरीदारी करते समय हर रुपया मायने रखता है, पांच दिन की यह सेल होम और पर्सनल केयर, प्रोसेस्ड फ़ूड, स्टेपल, डेयरी, होम और फ़ैशन कैटेगरी में आकर्षक



ऑफ़र ला रही है। यह ऑफ़र व्यक्तिगत डील से कहीं ज़्यादा है, जिससे ग्राहकों को पूरे शॉपिंग बास्केट में वैल्यू अनलॉक करने में मदद मिलती है। यह सेल परिवारों

अनदेखे ऑफ़र में शामिल हैं

- 5 kg बासमती चावल + 2.73 kg तेल,
- बिरिकट और वॉकलेट पर कोई भी 2 खरीदें, कोई भी 1 मुफ़्त पाएं
- 3.6 ₹ 5kg डिजर्टेंट कम से कम 33% की छूट पर
- टॉप ब्रांडेड शेम्पू पर प्लेट 60% की छूट
- 2 पीस स्टेनलेस स्टील ट्रिपली कुकवेयर कॉम्बो प्लेट Rs.999/- में

को ज़्यादा शॉपिंग करने, ज़्यादा बचत करने और खर्च किए गए हर रुपये का ज़्यादा फ़ायदा पाने में मदद करने के लिए डिज़ाइन की गई है। जिसमें रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ों और घर की ज़रूरतों पर ऑफ़र शामिल हैं। रिलायंस रिटेल

के श्रद्धह - ग़्रोसरी रिटेल, दामोदर मॉल ने कहा: > ' भारतीय घरों के लिए, खर्च किए गए हर रुपये से वैल्यू पाना कॉम्प्रोमाइज़ करने के बारे में नहीं है—यह इस बारे में स्मार्ट होने के बारे में है कि आप क्या खरीदते हैं, कब खरीदते हैं।

बजाज फाइनेंस एनसीडी जारी कर जुटायेगा 1,115 करोड़



मुंबई, 10 अगस्त गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी बजाज फाइनेंस गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) जारी कर 1,115 करोड़ रुपये जुटायेगी।

कंपनी की डिबेंचर आवंटन समिति ने सोमवार को एक लाख रुपये ऑफ़र मूल्य के 1,11,500 एनसीडी जारी करने के प्रस्ताव

को मंजूरी प्रदान की। इनका आवंटन निजी नियोजन के आधार पर किया गया है। शेयर बाजार बीएसई में सूचीबद्ध इन एनसीडी की अवधि 1,187 दिन की है। इन पर 7.78 प्रतिशत का सालाना ब्याज देय होगा। ब्याज की पहली किस्त का भुगतान 09 नवंबर 2026 को किया जायेगा। उसके बाद 09 नवंबर 2029 तक हर एक साल पर भुगतान होगा।

उदयनिधि नेतापुत्र से बने करुणानिधि के उत्तराधिकारी

चेन्नई. 4 अगस्त को डीएमके नेता और पूर्व डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन को चेन्नई पुलिस नीलांकरई स्थित उनके घर से ले गई।

हिरासत में लेने के बाद उन्हें तंजावुर ले जाया गया।

मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें 4 घंटे की पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया। देर रात उदयनिधि चेन्नई पहुंचे, जहां उनका थैंड वेलकम हुआ। इस बीच डीएमके नेता की हिरासत और रिहाई तक पूरे दिन

राजनीतिक ड्रामा चलता रहा। इन 10-12 घंटों में उदयनिधि के पॉलिटिकल इमेज में बड़ा बदलाव हुआ।

पुलिस हिरासत में जाने से पहले वह पूर्व सीएम स्टालिन के बेटे थे, जिन्हें डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष जैसे पद फैमिली गिफ्ट करने पर मिले थे। अब वह करुणानिधि की द्रविड़ पॉलिटिक्स के राजनीतिक उत्तराधिकारी बन गए, जो सत्ता से टकरा सकता है।

एमएलसी बनने के साथ दीपक का संकट खत्म

भाजपा के विधान परिषद सदस्य देवेश कुमार ने की थी सीट खाली

पटना. राज्यसभा सांसद उषेंद्र कुशवाहा के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री दीपक प्रकाश बिहार विधान परिषद के लिए मनोनीत किए गए हैं। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद सदस्य देवेश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।

उनके इस्तीफे के बाद चर्चा चल रही थी कि इस खाली सीट पर मंत्री दीपक प्रकाश को मनोनीत किया जा सकता है। अब विधान परिषद में मनोनीत होने के बाद दीपक प्रकाश की मंत्री पद की सदस्यता संबंधी संवैधानिक



बाधा दूर हो गई। भारतीय जनता पार्टी के विधायक देवेश कुमार द्वारा बिहार विधान परिषद से इस्तीफा देने के बाद बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के उच्च

सदन में प्रवेश का रास्ता साफ हो गया था। दीपक प्रकाश वर्तमान में बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री हैं। लेकिन वे विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं थे।

कुशवाहा परिवार ने ली राहत की सांस

विपक्ष का कहना है कि संवैधानिक आवश्यकताओं का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए जबकि सत्ताधारी एनडीए ने दावा किया है कि कानून के अनुसार सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। राजनीतिक विश्लेषक देवेश कुमार के इस्तीफे को बिहार सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम मान रहे थे। अब दीपक प्रकाश के विधान परिषद में मनोनीत होने से उनके मंत्री पद से संबंधित तात्कालिक संवैधानिक मुद्दा हल हो गया और कुशवाहा परिवार ने राहत की सांस ली।

विशेष दोनों नेताओं ने साथी चुप्पी, अटकलों का बाजार गर्म

पीके की सुनित्रा पवार से क्या बात हुई?

मुंबई. बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर की मुंबई यात्रा ने महाराष्ट्र की राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है।

प्रशांत किशोर ने गुरुवार को महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री और एनसीपी नेता सुनित्रा पवार और पार्थ पवार के साथ करीब छह घंटे तक बंद कमरे में लंबी बैठक की। बैठक में क्या चर्चा हुई, इस पर दोनों पक्षों ने आधिकारिक तौर पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन



राजनीतिक गलियारों में इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। खासकर इस बात को लेकर कि एनसीपी अब किस दिशा में आगे बढ़ेगी। सूत्रों के मुताबिक, बैठक

में एनसीपी के संगठन को मजबूत करने, पार्टी की भविष्य की रणनीति और आगामी स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई। यह भी माना

जा रहा है कि महाराष्ट्र में एनसीपी के संगठनात्मक ढांचे में बदलाव और पार्टी नेतृत्व को नए सिरे से मजबूत करने जैसे मुद्दों पर भी विचार-विमर्श हुआ। हाल ही में पार्टी के महिला, युवा और छात्र संगठनों में हुई नई नियुक्तियों को भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि बीजेपी के साथ बदलते समीकरण, शरद पवार गुट की गतिविधियां और आगामी जिला परिषद तथा पंचायत चुनावों को देखते हुए एनसीपी अपनी

राजनीतिक दिशा को लेकर नए विकल्पों पर मंथन कर रही है। बताया जा रहा है कि पार्टी के भविष्य के संगठनात्मक और चुनावी रोडमैप को लेकर अहम माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस द्वारा सुनित्रा पवार को गूंगी गुडिया कहे जाने के मुद्दे भी चर्चा हुईं। वहीं, यह भी चर्चा है कि निकाय चुनावों से पहले प्रशांत किशोर एनसीपी के साथ किसी बड़ी रणनीतिक भूमिका में नजर आ सकते हैं।

संगठन में बदलाव पर चर्चा

बता दें कि प्रशांत किशोर दिल्ली से चार्टर्ड प्लाइड से पार्थ के साथ पहुंचे थे। सूत्रों के मुताबिक, एनसीपी को पार्टी संगठन को फिर से खड़ा करने और अपनी चुनावी रणनीति को नए सिरे से तय करने में किशोर की सलाह काफी अहम हो सकती है। बताया जा रहा है कि पार्थ ने ही प्रशांत किशोर से संपर्क किया था, जिनके पवार परिवार के साथ कभीशा अछें संबंध रहे हैं। परिवार के करीबी एक सूत्र ने बताया कि एक विचार यह है कि राज्य एनसीपी नेतृत्व में बदलाव किया जाए और संगठन की कमान ऐसे व्यक्ति को सौंपी जाए जो कोई निर्वाचित प्रतिनिधि न हो।

अब विधानसभा सीट पर अखिलेश की नजर

लखनऊ. समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले अयोध्या को अपनी सबसे अहम राजनीतिक रणभूमि बना लिया है। लखनऊ में आयोजित ब्राह्मण सम्मेलन के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंच से पूर्व विधायक पवन पांडेय को अयोध्या से पार्टी का उम्मीदवार घोषित करने जैसे संकेत दिए।

उन्होंने कहा, पवन पांडेय अयोध्या से जीतने जा रहे हैं। उनके इस बयान पर सम्मेलन में

(अयोध्या) लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की थी।

अब तक राम मंदिर के मुद्दे पर अपेक्षाकृत सतर्क रहने वाली समाजवादी पार्टी इस बार कथित राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बना रही है। सपा का आरोप है कि इस मामले ने राम मंदिर प्रबंधन पर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी संसद से लेकर उत्तर प्रदेश विधानसभा तक



इस मुद्दे को उठा रही है। संसद परिसर में सपा सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया, जबकि विधानसभा में

भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा गया। सपा का मानना है कि राम मंदिर से जुड़े इस विवाद ने भाजपा को रक्षात्मक स्थिति में ला दिया है और यही मुद्दा आगामी विधानसभा चुनाव में भी प्रमुख रहेगा।

अयोध्या में फिर पवन पांडेय पर दांव

सपा ने संकेत दिया है कि अयोध्या विधानसभा सीट से एक बार फिर पवन पांडेय को उम्मीदवार बनाया जाएगा। पवन पांडेय 2012 में इस सीट से विधायक रह चुके हैं और हाल के वर्षों में अयोध्या में भूमि अधिग्रहण, विस्थापन और स्थानीय लोगों के मुद्दे उठाते रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट पर भाजपा की हार को विपक्ष ने बड़ा राजनीतिक संदेश माना था। सपा उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने भाजपा के ललू सिंह को हराया था। इसके बाद अब पार्टी की कोशिश विधानसभा चुनाव में भी इसी राजनीतिक बढ़त को दोहराने की है। हालांकि अयोध्या विधानसभा सीट पर भाजपा का मजबूत रिकॉर्ड रहा है। 1991 से 2007 तक भाजपा के ललू सिंह लगातार पांच बार विधायक बने।